आकाशवाणी

क्षेत्रीय समाचार एकांश

देहरादून (उत्तराखण्ड)

बृहस्पतिवार 28.11.2024

समय 1305

मुख्य समाचार :–

- गृहमंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर मसूरी पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 99वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को करेंगे संबोधित।
- प्रदेश में शत प्रतिशत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जिलावार कार्ययोजना बनाई जाएगी।
- उत्तराखंड में साल 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
- हल्द्वानी शहर में पहली दिसंबर से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ई–रिक्शा संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा।

गृह मंत्री उत्तराखंड दौरा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आज मसूरी पहुंच गए हैं। वे अब से कुछ देर में मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 99वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनज़र सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गए हैं।

इससे पहले, श्री शाह के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया।

कार्ययोजना

प्रदेश में शत प्रतिशत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जिलावार कार्ययोजना बनाई जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए डॉक्टर रावत ने इसके लिए आगामी 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाने को कहा, जिसमे 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों के भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, एन०एन०एम, आशा और आयुष्मान मित्रों का सहयोग लिया जाए। समीक्षा के दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी प्रगति वाले जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी चिकिसाधिकारियों को ठोस कार्ययोजना बनाकर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

सख्त कानून की आवश्यकता

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा क़ानूनों को और अधिक सख्त बनाए जाने की आवश्यकता है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी का एक बड़ा माध्यम है, लेकिन संपादकीय नियंत्रण न होने के कारण सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री का निर्बाध प्रसार हो रहा है। ओटीटी सामग्री के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म जिन देशों से आए हैं, उनकी और भारत की संस्कृति में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति को इस मामले को देखना चाहिए।

श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में ओटीटी मंचों के लिए आचार–संहिता बनाई है। इसमें ऐसी किसी भी सामग्री के प्रसारण की अनुमति नहीं है जो कानूनन प्रतिबंधित हो।

निरीक्षण

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून के देहराखास में बन रहे नए आढ़त बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पुराने आढ़त बाजार के कारण ट्रैफिक जाम कि समस्या बनी रहती है, जिसके कारण नया आढ़त बाजार बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें तीन सौ पचास से ज्यादा आढ़त व्यापारियों को शिप्ट किया जाएगा।

आढत बाजार में एक सौ छब्बीस करोड़ रुपए कि लागत से लगभग 10 हेक्टेयर में पांच सौ सत्तर गाड़ियों की पार्किंग, बेहतर रास्ते, अच्छे शौचालयों के साथ ही महिलाओं के लिए एक पिंक टॉयलेट का निर्माण अगले साल मई महीने तक पूरा कर लिया जाएगा।

सहकारिता वर्ष– 2025

उत्तराखंड में साल 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सहकारिता मंत्री धनसिंह रावत ने यह घोषणा की है। इसके तहत मार्च 2025 तक सभी गांवों और ग्राम सभाओं में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। देहरादून में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक की ओर से आयोजित एक दिवसीय सहकारिता कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर रावत ने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही सहकारिता के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, सहकारिता के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। पिछले सात से आठ सालो में सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और नवाचार के साथ कार्य हुए हैं, जिससे सभी सहकारी समितियां और जिला सहकारी बैंक लाभ में हैं।

इस अवसर पर सहकारिता सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर गांव में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन करना होगा। ग्रामीण स्तर पर किसानों को सहकारिता से जोड़ने से राज्य की समृद्धि सुनिश्चित होगी।

ई–रिक्शा संचालन पर रोक

हल्द्वानी शहर में पहली दिसंबर से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ई–रिक्शा संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यातायात को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने ई–रिक्शा चालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

पुलिस अधिक्षक, शहर, हरबंस सिंह ने बताया कि ई–रिक्शा चालकों को अनिवार्य रूप से अपने दस्तावेजों का सत्यापन भी कराना होगा। इसके अलावा, प्रशासन द्वारा निर्धारित वर्दी पहनना भी अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया, तो एक दिसंबर के बाद से हर दिन चेकिंग अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों का वाहन सीज करने के साथ–साथ उनका परमिट भी रद्द किया जाएगा। प्रशासन के साथ आयोजित बैठक में मौजूद ई–रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने सभी निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया है। इस निर्णय के बाद, शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की उम्मीद की जा रही है।

पिथौरागढ़ पर्यटन

पिथौरागढ़ जिले में आने वाले पर्यटकों की संख्या में इस बार उल्लेखनीय बढोतरी दर्ज की गई है। आदि कैलाश यात्रा के साथ ही जिले में अन्य यात्राओं में पिछले वर्षो की तुलना में इस वर्ष रिकार्ड यात्री यहां पहुंचे हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2022 में आदि कैलाश की यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या एक हजार 761 थी। लेकिन इस वर्ष तीस हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए हैं। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदि कैलाश के दौरे के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक पिथौरागढ पहुंच रहे हैं। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले सालों में और अधिक संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे।

वहीं, जिले के अन्य पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 2022 में जिले में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या एक लाख उन्नीस हजार थी, जो इस वर्ष बढ़कर एक लाख 88 हजार हो गई है।

ठोस कार्ययोजना

रुद्रप्रयाग जिले में कालीमठ घाटी के प्राचीन मठ–मंदिरों को तीर्थाटन और पर्यटन के नक्शे पर लाया जाएगा। इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी। केदारनाथ विधानसभा की नव निर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि कालीमठ घाटी के सभी प्राचीन मठ–मंदिरों को तीर्थाटन से जोड़ने के लिए तीर्थाटन सर्किट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और पर्यटन विभाग के सहयोग से इन सभी स्थलों का सर्वेक्षण कराया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर जरूरी सुविधाएं जुटाई जाएंगी।

कार्यशाला

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की ओर से उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन मुख्यालय पर ''पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना'' के तहत ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर सिस्टम विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में संपन्न इस कार्यशाला में यूपीसीएल के कर्मचारियों को इस योजना की तकनीकी और व्यावहारिक जानकारी दी गई। इसमें यूपीसीएल के लगभग 40 फील्डस्टाफ और इंजीनियरों ने हिस्सा लिया।

गौरतलब है कि पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक प्रदेशभर में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लगभग लगभग नौ हजार सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी क्षमता 32 मेगावाट की है। इस योजना से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को अब तक लगभग 73 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी दी जा चुकी है।